

उत्तरांचल शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग

संख्या 713 /XI/06/56(23)/2006
देहरादून, दिनांक 10 जून 2006
कार्यालय झाप

उत्तरांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार अथवा रोजगार अपना कर जीविकोपार्जन हेतु राज्य सरकार द्वारा " सार्वभौम रोजगार योजना " प्रारम्भ की गई है, जिसके संचालन हेतु शासन के सम्यक विचारोपरान्त निम्न मार्ग निर्देश जारी किये जाने के मुझे निदेश हुआ है :-

1- प्रस्तावना :-

उत्तरांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों, सार्वजनिक एवं निजी परिसम्पत्तियों एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध जनशक्ति एवं सामाजिक पूंजी पर आधारित यह रोजगार योजना ऐसे इच्छुक शिक्षित, अर्द्धशिक्षित एवं अशिक्षित युवक/युवतियों, पुरुषों एवं स्त्रियों को लक्षित करती है जो स्थानीय रूप से स्वरोजगार अथवा रोजगार अपनाकर जीविकोपार्जन करना चाहते हैं।

2-योजना क्षेत्र:-

सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य का ग्रामीण क्षेत्र।

3-पात्रता :-

ग्रामीण परिवार का कोई भी एक वयस्क सदस्य जो केन्द्र अथवा राज्य द्वारा प्रायोजित एवं सहायित किसी भी ऋण सह अनुदान, स्वरोजगार/रोजगार योजना का लाभार्थी न हो एवं सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र में नियमित रूप से सेवायोजित न हो, एवं स्वरोजगार हेतु इच्छुक हों।

4-आरक्षण :-

योजनान्तर्गत अनु0जाति तथा अनु0ज0जाति के लाभार्थियों का न्यूनतम प्रतिशत कमशः 18 व 3 रहेगा। कुल लाभार्थियों में कम से कम 33 प्रतिशत महिलायें तथा 3 प्रतिशत विकलांग होंगे।

5-अनुमन्यतायें :-

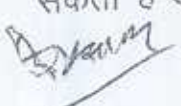
परियोजना प्रस्ताव के अनुसार चयनित क्रियाकलाप/गतिविधि के लिये प्रथम वर्ष में प्रति व्यक्ति रु0 7000/- (रु0 सात हजार मात्र) की सीमा तक अनुदान।

द्वितीय वर्ष में चयनित रोजगार क्रियाकलाप/गतिविधि की सफलता पर आधारित अधिकतम रु0 5000/- (रु0 पांच हजार मात्र) का प्रोत्साहन अनुदान।

तृतीय व अन्तिम वर्ष में चयनित रोजगार क्रियाकलाप/गतिविधि के सफल संचालन पर अधिकतम रु0 3000/- (रु0 तीन हजार मात्र) का प्रोत्साहन अनुदान।

परन्तु अनुदान की राशि किसी भी दशा में परियोजना लागत की 50 प्रतिशत राशि से अधिक नहीं होगी। परियोजना राशि के शेष भाग का निवेश लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जा सकता है अथवा वह इस हेतु बैंक से ऋण ले सकता है। बैंक ऋण की सीमा व्यक्तिगत

कमशः _____ 2 पर



स्वरोजगार योजनाओं में यथा निर्धारित होगी। बैंक वित्त पोषण को प्राथमिकता दी जायेगी।

स्नातक अथवा उससे अधिक शिक्षित लाभार्थियों के लिये अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान कुल देय अनुदान का 10 प्रतिशत होगा।

6-रोजगार क्रियाकलाप/गतिविधियाँ:-

1. बागवानी
- 2-जड़ी बूटी एवं रागी पादप कृषिकरण
2. वाणिज्यिक कृषि
- 3-पंचवक्की आधारित आर्थिक क्रियाकलाप
3. सूक्ष्म जल विद्युत योजना
4. शिल्प एवं कारीगरी पर आधारित आर्थिक क्रियाकलाप
5. खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्द्धन (value addition) सम्बन्धी आर्थिक क्रियाकलाप
6. कृषि, बागवानी, जड़ी-बूटी, पशुपालन हेतु निवेश सम्बन्धी सेवा व्यवसाय, एवं
- 7- अन्य कोई ऐसा क्रियाकलाप अथवा गतिविधि जिसे राज्य सरकार योजना के प्रयोजनार्थ सम्मिलित करे।

7-नोडल विभाग एवं जिले का नोडल अधिकारी:-

इस योजना का नोडल विभाग ग्राम्य विकास विभाग होगा। जिले में जिलाधिकारी इस योजना के नोडल अधिकारी होंगे। क्रियान्वयन में सुगमता के लिये जिलाधिकारी कतिपय अथवा समस्त अधिकार मुख्य विकास अधिकारी के पक्ष में प्रतिनिधानित कर सकेंगे।

8-आवेदन एवं आवेदनों का निस्तारण :-

इच्छुक पात्र बेरोजगार व्यक्ति चयनित आर्थिक क्रियाकलाप/गतिविधि, उपलब्ध प्राकृतिक, सार्वजनिक व निजी संसाधनों एवं जनशक्ति व सामाजिक पूंजी का उल्लेख करते हुये आवेदन खण्ड विकास अधिकारी, रेखीय विभाग, जिला विकास अधिकारी अथवा परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के माध्यम से जिलाधिकारी अथवा मुख्य विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। चयनित क्रियाकलाप/गतिविधि की सम्भावनाओं के आधार पर रेखीय विभाग परियोजना प्रस्ताव 15 दिवस के भीतर सम्पूर्णता में जिलाधिकारी को स्वीकृतार्थ प्रस्तुत करेंगे। परियोजना प्रस्तावों के परीक्षण एवं उन पर संस्तुति हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्न समिति विचार करेगी:-

जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी

अध्यक्ष

परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0

सदस्य सचिव

रेखीय विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी

सदस्य

कमश:-3

महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र

सदस्य

जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक

सदस्य

परियोजना प्रस्ताव पर अंततः स्वीकृति जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी। बैंक से वित्त पोषण वांछित होने की स्थिति में परियोजना प्रस्ताव की एक-एक प्रति सम्बन्धित बैंक की शाखा एवं जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक को प्रेषित की जायेगी। सम्बन्धित बैंक की शाखा द्वारा एक माह के भीतर परियोजना प्रस्ताव पर निर्णय लिया जायेगा। बैंक से स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में अनुदान की राशि सम्बन्धित शाखा को भेज दी जायेगी। अनुदान की राशि पर न तो ब्याज देय होगा और न ही ब्याज वसूला जायेगा। अनुदान की राशि का समायोजन back ended subsidy के रूप में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जायेगा।

परियोजना प्रस्ताव के अनुसार परियोजना राशि सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा एक मुश्त अथवा दो किश्तों में कार्यान्वयन की सफलता के आधार पर लाभार्थी के खाते में अवमुक्त की जायेगी। बैंक अधिकारी एवं रेखीय विभाग के अधिकारी परियोजना के विभिन्न चरणों का निरीक्षण व परीक्षण कर सकेंगे।

परियोजना राशि के दुरुपयोग की स्थिति में ऋण की अवशेष राशि एवं अनुदान की सम्पूर्ण राशि सब्याज भूराजस्व की बकाया राशि की भांति वसूली जा सकेगी।

9-योजना की अवस्थापना :-

इस योजना के लिये योजना अवस्थापना की कोई पृथक व्यवस्था नहीं की जा रही है। चयनित कियाकलाप/गतिविधि के अनुसार रेखीय विभागों अथवा मिलती जुलती योजना का संचालन करने वाले विभागों की योजना अवस्थापना का लाभ इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु उठाया जा सकता है।

10-प्रशिक्षण :-

जिले में अवस्थित रेखीय विभागों एवं मिलती जुलती योजनाओं का संचालन करने वाले विभागों के चालू प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इस योजना के लाभार्थियों को सम्मिलित किया जा सकता है।

11-सम्बन्धित विभागों की प्रतिबद्धता :-

चयनित कियाकलापों से सम्बन्धित विभाग एवं रेखीय विभाग इस योजना के क्रियान्वयन



क्रमशः—4—

के लिये पूर्णतः प्रतिबद्ध होंगे। जिलाधिकारी असहयोग करने वाले विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध स्वयं कार्यवाही के लिये सक्षम होंगे। उचित प्रकरणों में ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध शासन स्तरीय कार्यवाही की संस्तुति शासन को की जायेगी।

12-पूर्वगामी एवं पश्चगामी अन्तर्सम्बन्धन :-

जिले में अवस्थित सम्बन्धित विभागों एवं रेखीय विभागों के चालू कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध ऐसे अन्तर्सम्बन्धनों का लाभ इस योजना के अधीन लिया जा सकेगा।

13-अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :-

शासन स्तर पर इस योजना की समीक्षा एवं अनुश्रवण अन्य विकास योजनाओं की भाँति किया जायेगा।

जिलाधिकारी प्रतिमाह योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा कर मासिक प्रगति विवरण ग्राम्य विकास निदेशालय, पौड़ी के माध्यम से शासन को भेजेंगे। ग्राम्य विकास निदेशालय मासिक विवरण प्रपत्र निर्धारित कर जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। क्रियान्वयन के आरम्भिक वर्षों में प्रत्येक जिलाधिकारी से यह अपेक्षित होगा कि वे योजना के और अधिक प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन एवं कठिनाई निवारण हेतु सुझाव शासन को प्रेषित करते रहें।

फील्ड स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वयं पर्याप्त संख्या में सत्यापन एवं मूल्यांकन किया जायेगा। सत्यापन मानक निम्नवत हैं :-

क्र०सं	अधिकारी का पदनाम	सत्यापन का प्रतिशत
1.	जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	10 प्रतिशत
2.	अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी	10 प्रतिशत
3.	रेखीय विभाग के अधिकारी/उपजिलाधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी (सम्बन्धित के मध्य सत्यापन का विभाजन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा)	शत प्रतिशत

पी०के० महान्ति

सचिव

संख्या 713 /XI/06/56(23)/2006 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ प्रेषित :-

1:- समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव उत्तरांचल शासन।



- 2- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तरांचल पौड़ी ।
- 3- आयुक्त गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल ।
- 4- समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल ।
- 5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी / अधिशासी निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण उत्तरांचल ।
- 6- समस्त परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तरांचल ।
- 7- निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तरांचल देहरादून ।
- 8- समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तरांचल ।
- 9- निजी सचिव-मुख्यमंत्री उत्तरांचल को मा10 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
- 10- निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ ।
- 11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4 ।
- 12- नियोजन विभाग ।
- 13- समाज कल्याण विभाग ।
- 14- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से ,


(शैलेश कुमार पन्त)

अनुसचिव

